सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

RNI No: UPHIN/2023/86769

www.swarajindianews.com

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

मूल्यः ₹ 02

सांध्यकालीन समाचार पत्र

स्वराज इंडिया

कानपुर, गुरुवार, 19 जून, 2025
वर्षः 02, अंकः 169, पृष्ठः 8+4

ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का यूपी से खास कनेक्शन » Pg 12

इनसाइड अघोषित 'प्रतिबंध राज' में फंस गई अयोध्या... » Pg 10

चिट्ठी ना कर पाई डिफेंड कानपुर सीएमओ हुए सस्पेंड

श्रावस्ती में एसीएमओ के पद पर तैनात डॉक्टर उदयनाथ को कानपुर का सीएमओ बनाया

» अनूप अवस्थी, स्वराज इंडिया न्यूज

कानपुर। अंततः तमाम विवादों में घिरे कानपुर के सीएमओ डॉक्टर हरी दत्त नेमी को सस्पेंड कर दिया गया। उनकी जगह श्रावस्ती में एसीएमओ के पद पर तैनात डॉक्टर उदयनाथ को कानपुर का मुख्य चिकित्सा अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है।

यूं तो डॉक्टर हरिदत्त नेमी का कानपुर में सीएमओ के रूप में 6 माह का कार्यकाल विवादों से घिरा रहा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में तो विवादों की पराकाष्ठा हो गई। सीएमओ डॉक्टर नेमी की कारगुजारियों ने न केवल स्वास्थ्य महकमें की किरकिरी कराई बल्कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की फजीहत भी करा दी। इतना ही नहीं सीएमओ साहब के मुद्दे पर कानपुर के विधायक भी दोफाड़ नजर आए। जिससे भाजपा को भी अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा। कानपुर के सबसे कद्दावर भाजपाई विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की छवि पर भी इस प्रकरण ने विपरीत प्रभाव डाला। मामला स्वास्थ्य विभाग के मंत्री डिप्टी सीएम बृजेश पाठक से होता हुआ मुख्यमंत्री तक पहुंचा। जिसके बाद कार्यवाही अवश्यंभावी थी जो आज निलंबन के रूप में परिणति को प्राप्त हुई।

गहराया विवाद

डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने अपने बचाव के लिए विधायकों और प्रभावशाली लोगों को जब अपना दुखड़ा सुनाया और डीएम के विषय में अनर्गल बातें कहीं तो कथित रूप से उनके दो ऑडियो वायरल हुए। जिसमें एक में वो डीएम कानपुर नगर के लिए आपत्तिजनक बातें बोल रहे थे तो दूसरे में कमाई के जुगाड़ की बातें करते सुनाई दे रहे थे। उनके द्वारा इन ऑडियो के विषय में कहा गया कि आवाज उनकी ना होकर एआई जेनरेटेड है। लेकिन इस पर विधिक कार्यवाही न करने के चलते उनकी दलील में दम नजर नहीं आया।

निलंबित सीएमओ की कारगुजारी : एक तरफडीएम जितेंद्र प्रताप सिंह कानपुर की प्रशासनिक मशीनरी और स्वास्थ्य व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए निरीक्षण कर निर्देश पर निर्देश दे रहे थे तो दूसरी ओर सीएमओ उनके निदेशों को ठेंगा दिखाते जा रहे थे। डीएम ही नहीं सीएमओ की कार्यशैली की आलोचना उनके अधीनस्थ भी कर रहे थे। स्वास्थ्य महकमें से जुड़े ठेकेदार भी कुछ दबी जुबान से तो कुछ बाकायदा लिखित शिकायत कर सीएमओ की ईमानदारी पर सवालिया निशान लगा रहे थे। लगातार घोर लापरवाही और नियम विरुद्ध कार्यशैली को देखते हुए अप्रैल माह में डीएम कानपुर नगर ने एक विस्तृत रिपोर्ट के साथ सीएमओ को हटाने की संस्तुति स्वास्थ्य सचिव को प्रेषित कर दी। स्वयं को घिरता देख और विभागीय कार्रवाई को अवश्यंभावी मानते हुए सीएमओ ने प्रभावशाली और सत्ता पक्ष के माननीयों की शरण में जाने का रास्ता चुना।

छपते छपते

निलंबन आदेश आने के बाद निवर्तमान सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीएम पर गंभीर आरोप लगाए और आदेश के खिलाफ न्यायालय जाने की बात कही। डॉ. नेमी ने पत्रकारों को सूबे के मुख्यमंत्री को उनके द्वारा लिखी चिट्ठी की छायाप्रति भी उपलब्ध कराई।

कानपुर में चलीं चिट्ठी मिसाइल

ऑडियो वायरल होने के बाद नुकसान की भरपाई के लिए अंतिम प्रयास के रूप में डॉक्टर हरी दत्त नेमी ने सत्ता पक्ष के विधायकों को टूल के रूप में इस्तेमाल किया। पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से डिप्टी सीएम के लिए अपने पक्ष में चिट्ठी लिखवाई और फिर ऐसा लगता है कि विस अध्यक्ष की चिट्ठी दिखाकर एमएलसी अरुण पाठक और विधायक सुरेंद्र मैथानी से भी चिट्ठी लिखवा कर वायरल कर दी। लेकिन सीएमओ साहब का यह दांव दो तरह से उल्टा पड़ गया। पहले तो वह राज्य सेवा नियमावली के अनुसार दोषी हो गए, दूसरा कुछ विधायकों ने उनका विरोध करते हुए सीधे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर उनके कारगुजारी की जांच की संस्तुति कर दी।

निलंबन का आधार

- सीएमओ डा. हरिदत्त नेमी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र के आधार पर रिक्त पदों पर की जाने वाली भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया के विपरीत पदों का विज्ञापन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यूपी की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया।
- जिला स्वास्थ्य समिति और मुख्य विकास अधिकारी कानपुर नगर के स्पष्ट आदेश के बाद भी आयुष परीक्षा के बाद किए गए साक्षात्कार का परिणाम चार दिन में जारी नहीं किया जिससे भर्ती प्रक्रिया बाधित हुई।
- वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी को वित्तीय एवं पदेन कार्यों से मुक्त कर गैर वित्त सेवा क्षेत्र में काम कराया।

ऑनर किलिंग

पड़ोसी लड़के से शादी की जिद पड़ी भारी

शिवानी को परिवार ने ही गला घोंटकर मार डाला

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

गाजियाबाद। बागपत के बड़ौत के लुहारी गांव में पड़ोसी युवक से शादी की जिद पर अड़ी शिवानी (21) को उसके मां बाप, भाई व फुफेरी बहन ने गला घोंट मार डाला। इसके बाद रात में शव जलाकर यमुना में बहा दिया।

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी युवती की परिवार ने हत्या कर दी और लाश जला दी। परिवार ने युवती की अस्थियां भी विसर्जित कर दीं। प्रेमी ने जब मामले की जानकारी पुलिस को दी तो खुलासा हुआ। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी मां-बाप को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मृतक का भाई और फुफेरी बहन फरार हैं। वो भी हत्याकांड में शामिल हैं।

लुहारी गांव निवासी अंकित प्रजापति ने बताया कि पड़ोस की शिवानी कश्यप के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों पिछले डेढ़ साल से शादी करना चाहते थे। कुछ दिन पहले शिवानी के परिजनों को उनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल गया तो उन्होंने शिवानी का घर से निकलना बंद कर दिया। अंकित का आरोप है कि परिवार के लोग शिवानी की पिटाई करने लगे, लेकिन शिवानी शादी की जिद पर अड़ी रही। मंगलवार रात परिवार वालों ने घर में शिवानी की हत्या कर दी। बुधवार की सुबह शिवानी का मोबाइल बंद मिलने पर अंकित ने पुलिस को घटना की जानकारी दी।

बताया गया कि मृतका और उसका प्रेमी दोनों की जाति अलग-अलग है और उनके मकानों में दो मकान ही बीच में हैं। शिवानी दसवीं तक पढ़ाई कर चुकी है और अंकित मजदूरी करता है। एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि मृतका के पिता और मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

मां-बाप और बहन ने पकड़े हाथ-पैर, भाई ने दबा दिया गला

पुलिस के अनुसार चारों आरोपियों ने मिलकर शिवानी की हत्या की। पिता संजीव, मां बबीता और फुफेरी बहन ने शिवानी के हाथ-पैर पकड़े और भाई रवि ने अपने हाथों से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद करीब एक घंटे तक चारों शव के पास बैठे रहे और बाद में मामला दबाने के लिए शव को यमुना किनारे लेकर चले गए।

गांव वाले परिवार पर कसते थे तंज

आरोपी संजीव ने बताया कि मृतका शिवानी और अंकित के बीच काफी समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। इस बारे में करीब डेढ़ साल पहले गांव के काफी लोगों को पता चल गया था। शिवानी के परिवार वालों पर रास्ते में गांव के लोग तंज कसते रहते थे। बड़ौत के लुहारी गांव में शिवानी की हत्या के बाद उसके प्रेमी अंकित को अपनी हत्या होने का डर सताने लगा है। अंकित ने बुधवार शाम को अपना वीडियो जारी कर खतरा जताया। अंकित ने बताया कि शिवानी के परिवार वाले उसकी भी हत्या कर सकते हैं। अगर उसके साथ कोई घटना होती है तो इसके जिम्मेदार शिवानी के परिवार वाले होंगे। अंकित ने बताया कि कई साल से दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग चल रहा था। शिवानी को अपनी हत्या होने का खतरा सताने लगा था, इसके लिए शिवानी ने पहले बताया भी था।

कानपुर के हिस्ट्रीशीटरों की निगरानी करेगी पुलिस की 'दिव्य दृष्टि'

निर्मल तिवारी / स्वराज इंडिया

कानपुर। हिस्ट्रीशीटर्स अपराधियों पर नजर रखने के लिए कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में तकनीक आधारित नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। जिसे नाम दिया गया है दिव्यदृष्टि। यह जानकारी एक प्रेस वार्ता में कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने साझा की। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की उच्च तकनीक आधारित यह व्यवस्था पुलिस और हिस्ट्रीसीटर दोनों के लिए फायदेमंद होगी।

विशेष रूप से लंबे समय से अपराध से तौबा कर सामान्य जीवन जी रहे भूतपूर्व अपराधियों के लिए यह योजना अभूतपूर्व रूप से फायदेमंद होगी। कानपुर पुलिस कमिश्नर का कहना है यदि यह प्रयोग सफल रहा तो इस योजना का दूसरा चरण लागू किया जाएगा। जिसमें डिवाइस का उपयोग कर हिस्ट्रीशीटर्स के साथ ही जिलाबदर और पेट्रोल पर छूटे अपराधियों की भी सटीक निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी।

» दिव्यदृष्टि तकनीक आधारित निगरानी की व्यवस्था है
» भूतपूर्व अपराधियों को होगा योजना से अभूतपूर्व लाभ
» पुलिस को भी हिस्ट्रीशीटर्स पर नजर रखने में होगी आसानी
» प्रयोग सफल रहा तो दूसरे चरण में डिवाइस का हो सकता है उपयोग

जानिए हिस्ट्रीशीटर्स पर निगरानी की पुरानी व्यवस्था

परंपरागत रूप से हिस्ट्रीशीटर अपराधियों की निगरानी की मैन्युअल व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था में हिस्ट्रीशीटर्स अपराधी को नियमित रूप से थाने में हाजिरी लगानी होती है। बीट पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्र में रहने वाले हिस्ट्रीसीटर अपराधी के घर और मुहल्ले में जाकर उसकी गतिविधियों की जानकारी करते हैं और थाने में हिस्ट्री सीट रजिस्टर में प्राप्त जानकारी दर्ज कराते हैं।

कैसे काम करेगी कानपुर पुलिस की दिव्य दृष्टि

कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की यह व्यवस्था लगभग वैसी ही है जैसे हम सब अपने मोबाइल पर घर के अन्य सदस्यों की लाइव लोकेशन गूगल मैप के सहारे देखते रहते हैं। पुलिस आयुक्त ने दिव्यदृष्टि के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान दौर तकनीक का है। ऐसी तमाम तकनीक उपलब्ध हैं जिससे हम जीपीएस के माध्यम से किसी की भी लोकेशन जान सकते हैं। लोकेशन आधारित सेवाएं बहुत लोकप्रिय हैं। इस योजना में गूगल प्लेटफार्म का उपयोग कर निगरानी की जाएगी। इस वैकल्पिक योजना में शामिल होने वाले हिस्ट्रीशीटर को अपना मोबाइल नंबर देना होगा।

गूगल मैप के सहारे थाने में लगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर उक्त नंबर की लाइव लोकेशन नजर आएगी। पुलिस आयुक्त के अनुसार यह प्रायोगिक व्यवस्था है। इसमें मोबाइल डिस्चार्ज होने और नेटवर्क बाधित होने जैसी समस्याएं आ सकती हैं। जिसे हम रिव्यू करेंगे। साथ ही पुलिस समय-समय पर वीडियो कॉल कर हिस्ट्रीशीटर का भौतिक सत्यापन भी सुनिश्चित करेगी।

फेज-2 में जिला बदर और पैरोल पर छूटे अपराधियों की भी होगी सटीक निगरानी

फिलहाल व्यवस्था वैकल्पिक

क्योंकि पुलिस रेगुलेशन एक्ट में इस तरह निगरानी का प्रावधान नहीं है, इसलिए शुरुआती चरण में यह व्यवस्था वैकल्पिक होगी। व्यवस्था खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिन्होंने अपराध से तौबा कर ली है और सामान्य जीवन जी रहे हैं।

उन्हें इस योजना के अंतर्गत अपनी प्राइवेसी मेंटेन रखने, बार-बार थाने जाकर हाजिरी लगाने और पुलिस कर्मियों के बार-बार घर पहुंचने जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी। कानपुर पुलिस को उम्मीद है कि बड़ी संख्या में हिस्ट्रीशीटर कानपुर पुलिस की इस अनूठी दिव्यदृष्टि योजना को अपनाएंगे।

योजना में शामिल होने के लिए भरना होगा सहमति पत्र

कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की इस दिव्यदृष्टि योजना के माध्यम से अपनी निगरानी को सहमत हिस्ट्रीशीटर को एक सहमति पत्र भरना होगा और साथ ही उपयोग किये जा रहे मोबाइल नंबर की जानकारी पुलिस को देनी होगी।

प्रयोग सफल रहा तो लागू होगा द्वितीय चरण

पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने योजना की जानकारी साझा करते हुए बताया कि दिव्यदृष्टि योजना का यह प्रायोगिक चरण सफल रहा तो इसका फेज दो भी लागू किया जाएगा। जिसमें डिवाइस के माध्यम से पुलिस हिस्ट्रीशीटर के साथ-साथ जिला बदर अपराधियों और पैरोल पर छूट बंदियों की सतत निगरानी की व्यवस्था शुरू करेगी।

जिससे जिला बदर अपराधियों को जिले से बाहर रखने और पैरोल पर छूटे बंदियों को निर्देशित स्थान तक ही सीमित रखने की व्यवस्था सटीकता के साथ सुनिश्चित हो सकेगी।

अविंचल प्रताप सिंह को एसडीएम सदर बनाया

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। सदर तहसील में लंबे समय से तैनात एसडीएम रितु प्रिया को हटाकर घाटमपुर भेजा गया है। उनकी जगह पर घाटमपुर के अविंचल प्रताप सिंह को एसडीएम सदर बनाया गया है। इसी तरह से तहसीलदार सदर रितेश कुमार सिंह का तबादला गाजियाबाद हो गया है। उनकी जगह पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण से आए विनय द्विवेदी को तहसीलदार सदर बनाया गया है। तहसीलदार घाटमपुर लक्ष्मी नारायण बाजपेई का तबादला हाथरस होने की वजह से हमीरपुर से आए अनुभव चंद्रा को तहसीलदार घाटमपुर बनाया गया है।

फतेहपुर में दर्दनाक हादसा:मिट्टी की टीला ढहने से मलबे में दबकर तीन लोगों की मौत

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। कानपुर से सटे फतेहपुर जिले के किशनपुर में बुधवार को टीला ढहने से मिट्टी में दबकर तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि बुधवार को रात में हुई बरसात के कारण कगार की मिट्टी नम हो गई थी। अचानक ही कगार फट गया और तीनों चरवाहे नीचे गिर गए। ऊपर से मलबा गिरने पर तीनों चरवाहे नीचे दब गए।

आस-पास मवेशी चराने वाले लोगों ने आवाज सुनी तो भागकर मौके पर गए। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद मलबे में दबे तीनों शव निकाले। घटना की जानकारी मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया।

घटनास्थल पर क्षेत्र के लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि फतेहपुर जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र स्थित भसरौल गांव में रमेश धोबी (54), दुलारे पासी (55) और शिव मोहन यादव (56) मिट्टी के टीले पर आराम कर रहे थे तभी वह अचानक ढह गया और मिट्टी में दबने से तीनों की मौत हो गई। पुलिस क्षेत्राधिकारी (खागा) ब्रज मोहन राय ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को मिट्टी से बाहर निकाला।

नगर निगम की जमीनों पर केडीए दिखा रहा अपना मालिकाना

» नगर विकास मंत्री और प्रमुख सचिव ने केडीए और नगर निगम की जमीन के मुद्दे पर की वर्चुअल बैठक

» वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनी समस्या, पार्षद वेलफेयर ने भी समस्याओं से कराया अवगत

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर सिटी में नगर निगम और केडीए के बीच चल रहा जमीनों का विवाद शासन स्तर पर भी पहुंच गया है। नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने जमीनों को लेकर नगर विकास मंत्री और प्रमुख सचिव के सामने अपना पक्ष रखा। इस दौरान पार्षद वेलफेयर के पदाधिकारियों ने भी जमीनों पर केडीए की मनमानी का आरोप लगाया। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने जल्द ही शासन स्तर पर सम्बन्धित प्रकरणों का निर्णय लिये जाने आश्वासन दिया।

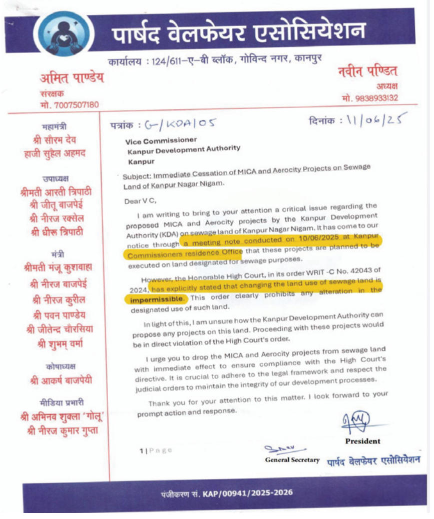
पार्षद वेलफेयर एसोसियेशन
कार्यालय : 124/611–ए–बी ब्लॉक, गोविन्द नगर, कानपुर
अमित पाण्डेय
संरक्षक
मो. 7007507180
नवीन पण्डित
अध्यक्ष
मो. 9838933132

महामंत्री
श्री सौरभ देव
हाजी सुहैल अहमद
उपाध्यक्ष
श्रीमती आरती त्रिपाठी
श्री जीतू बाजपेई
श्री नीरज रक्सेल
श्री धीरू त्रिपाठी
मंत्री
श्रीमती मंजू कुशवाहा
श्री नीरज बाजपेई
श्री नीरज कुरील
श्री पवन पाण्डेय
श्री जीतेन्द चौरसिया
श्री शुभम् वर्मा
कोषाध्यक्ष
श्री आकर्ष बाजपेयी
मीडिया प्रभारी
श्री अभिनव शुक्ला 'गोलू'
श्री नीरज कुमार गुप्ता

पत्रांक : G-/KDA/05
दिनांक : 11/06/25

Vice Commissioner
Kanpur Development Authority
Kanpur

Subject: Immediate Cessation of MICA and Aerocity Projects on Sewage Land of Kanpur Nagar Nigam.

Dear V C,

I am writing to bring to your attention a critical issue regarding the proposed MICA and Aerocity projects by the Kanpur Development Authority (KDA) on sewage land of Kanpur Nagar Nigam. It has come to our notice through a meeting note conducted on 10/06/2025 at Kanpur Commissioners residence Office that these projects are planned to be executed on land designated for sewage purposes.

However, the Honorable High Court, in its order WRIT -C No. 42043 of 2024, has explicitly stated that changing the land use of sewage land is impermissible. This order clearly prohibits any alteration in the designated use of such land.

In light of this, I am unsure how the Kanpur Development Authority can propose any projects on this land. Proceeding with these projects would be in direct violation of the High Court's order.

I urge you to drop the MICA and Aerocity projects from sewage land with immediate effect to ensure compliance with the High Court's directive. It is crucial to adhere to the legal framework and respect the judicial orders to maintain the integrity of our development processes.

Thank you for your attention to this matter. I look forward to your prompt action and response.

President
General Secretary
पार्षद वेलफेयर एसोसियेशन
1 | Page

पंजीकरण सं. KAP/00941/2025-2026

बीते दिन केडीए उपाध्यक्ष को पत्र भेजा

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद पार्षद वेलफेयर के अध्यक्ष अमित पांडे और अन्य अफसर

नगर निगम मुख्यालय स्थित सभागार कक्ष में सम्भव पोर्टल पर दर्ज प्रकरण की वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिये बैठक हुई। इसमें नगर विकास मंत्री अरविन्द कुमार शर्मा एवं प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग अमृत अभिजात से नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने नगर निगम के प्रकरण पर अपना पक्ष रखा। पार्षद वेलफेयर एसाेसिएशन के पदाधिकारियों को भी इस बैठक में जुड़ने को कहा गया था जिसपर उन्होंने भी मंत्री को पूर्व में दिये तीन पत्रों पर अपनी बात रखी। एसोसिएशन के संरक्षक अमित पाण्डेय और अध्यक्ष नवीन पण्डित ने बैठक में कहा कि कानपुर नगर निगम एवं केडीए के विवाद आयुक्त कानपुर मण्डल को भेजे जाते हैं। क्योंकि आयुक्त कानपुर मण्डल कानपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष है। इसलिये उनके द्वारा कानपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में निर्णय लिया जाता है। इसलिये किसी अन्य अधिकारी को कानपुर नगर निगम एवं कानपुर विकास प्राधिकरण के विवादों पर नियुक्त किया जाए।

केडीए द्वारा मनमानी कर जमीनों पर लाई जा रही परियोजना

नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि जाजमऊ में नगर निगम की सीवेज फार्म की 1200 एकड़ भूमि है। फिर भी केडीए ने अपनी बोर्ड बैठक में दो परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। बताया कि यह भूमि सीवेज फार्म है और हाई कोर्ट इलाहाबाद के पारित आदेश में भूमि का प्रयोग बदला नहीं जा सकता है। पदाधिकारियों ने आरोप लगाते हुये कहा कि केडीए मनमानी करते हुए परियोजनाओं का लागू करा रहा है। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में भी भूमि सम्बन्धी विवाद आये थे। केडीए को ग्राम समाज एवं इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की भूमि का अधिकार दे दिया गया है, ये व्यवस्था सिर्फ कानपुर में है, अन्य 16 नगर निगमों में नहीं।

74वां संशोधन लागू हो, महापौर ने पंचकुला में उठाया मुद्दा

74वां संशोधन लागू होने की वजह से मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के शहर आगे बढ़ते जा रहे हैं जबकि शहर पिछड़ रहा है। जब स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग की बारी आती है तो सभी प्रदेश के शहर को समान आधार से ही रैंकिंग में जोड़ा जाता है। इस वजह से हम नीचे आते हैं। जबकि इंदौर पहले नंबर पर काबिज हो जाता है। यह मुद्दा रविवार को पंचकुला में हुई आल इंडिया मेयर एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक महापौर प्रमिला पांडेय ने उठाया है। महापौर ने कहा कि इसलिये जहां 74वां संशोधन लागू है उन शहरों की स्वच्छता रैंकिंग अलग की जाए जब कि हमारे जैसे शहरों की रैंकिंग अलग जारी की जाए। उन्होंने बताया कि 264 महापौरों के सामने यह मुद्दा उठाया है। इसपर शहरी विकास मंत्रालय को जल्द प्रस्ताव देंगे। 74वां संशोधन लागू होने से जहां नगर निगम की शक्तियां बढ़ेंगी वहीं आम लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने में मदद मिलेगी।

विक्षिप्त वृद्ध को जीआरपी ने सकुशल किया बरामद

स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर। मंगलवार की शाम करीब 7:20 बजे एक महिला ज्ञानती कुशवाहा, पत्नी गणेश कुशवाहा (निवासी - गौरा दमकी टोला, थाना कटिया, जिला गोपालगंज, बिहार) GRP थाना कानपुर सेंट्रल पहुँचीं और सूचना दी कि उनके 60 वर्षीय पति गणेश कुशवाहा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर स्थित वाटर कूलर के पास से लापता हो गए हैं। उन्होंने बताया कि उनके पति मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और इलाज के लिए वापी (गुजरात) जा रहे थे।

सूचना मिलते ही ड्यूटी पर तैनात उप निरीक्षक संदीप कुमार तिवारी ने QRT टीम के साथ – हे.का. मोहम्मद आसिफ, हे. कां. शिव सिंह एवं हे. कां. सतीश यादव – तत्काल हरकत में आते हुए गुमशुदा की तलाश शुरू कर दी ।जांच के दौरान महिला ने बताया कि गुमशुदा के पास एक मोबाइल फोन है, किंतु नंबर याद न होने के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा था। महिला के पास उपलब्ध आधार कार्ड में अंकित नंबर से संपर्क साधा गया, जिससे गुमशुदा व्यक्ति से बात संभव हो सकी, हालांकि वह सही स्थान बता पाने में असमर्थ थे इस बीच गुमशुदा के पास मौजूद एक अन्य व्यक्ति, विकास निषाद (पुत्र रामकुमार, निवासी – नथापूर्वा, गंगा बैराज, कानपुर) से संपर्क करने पर सही लोकेशन प्राप्त हुई। तत्पश्चात, पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए एक घंटे के भीतर गुमशुदा गणेश कुशवाहा को इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, ट्रैफिक लाइन (झकरकटी–रामादेवी सड़क के पास) से

सकुशल बरामद कर लिया ।गणेश कुशवाहा की पहचान उनकी पत्नी ज्ञानती कुशवाहा द्वारा की गई, जिसके बाद उन्हें सुरक्षित सुपुर्द कर दिया गया। परिजनों ने जीआरपी कानपुर सेंट्रल की त्वरित और संवेदनशील कार्यवाही की भूरि–भूरि प्रशंसा की।

सीएमओ से ज्यादा उनकी कुर्सी की रही चर्चा !

सीएमओ के पक्ष में चिट्ठी लिखने वाले एमएलसी अरुण पाठक और डीएम कानपुर नगर मौजूद रहे एक बैठक में

मुख्य संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। डीएम और सीएमओ विवाद में विधायकों नेताओं की समर्थन व विरोध स्वरूप चिट्ठियों के वायरल होने के बाद कल का दिन अपेक्षाकृत शांत रहा। एक दिलचस्प वाकये के रूप में कल एक अद्भुत दृश्य भी सामने आया। साथ ही कल सीएमओ साहब से ज्यादा चर्चा में सीएमओ साहब की कुर्सी रही। दोनों ही खबरें आपको विस्तार से बताते हैं। पहले बात उस दिलचस्प वाकये की?, दरअसल कल सीएमओ के पक्ष में चिट्ठी लिखने वाले एमएलसी अरुण पाठक और कानपुर के डीएम साहब एक सरकारी बैठक में काफी समय तक एक साथ रहे।

4 फरवरी 2025

सीएमओ कुर्सी की कल की फोटो

कानपुर नगर के सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रतिनिहित विधायन समिति की कल बैठक थी। जिसमें एमएलसी अरुण पाठक सभापति के रूप में बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे और पूरे प्रशासनिक अमले के साथ कानपुर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रसाद सिंह भी बैठक में उपस्थित रहे। सीएमओ सीएमओ साहब का खेमा कल अपेक्षाकृत शांत रहा और सोशल मीडिया पर सीएमओ से ज्यादा सीएमओ की कुर्सी चर्चा में रही।

दरअसल कल सीएमओ कानपुर नगर डॉक्टर हरिदत्त नेमी को संचारी रोग के संबंध में एक प्रेस कांफ्रेंस करनी थी। पीसी के लिए जब पत्रकार सीएमओ ऑफिस पहुंचे तो पता चला जिले की सेहत ठीक रखने वाले विभाग के मुखिया की तबियत नासाज होने के चलते वह अवकाश पर हैं सबसे मजेदार बात यह है कि सुबह सीएमओ ऑफिस में बना खाली कुर्सियों का वीडियो दोपहर होते-होते सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ वायरल हो गया कि सीएमओ साहब ने विवाद उत्पन्न होने के बाद अपनी कुर्सी पर भगवा कलर का कवर डाल दिया और उनके भगवा प्रेम को सूबे के मुखिया से जोड़कर बताया जाने लगा। इसकी शुरुआत एक वरिष्ठ पत्रकार निक की जो बड़े-बड़े नामी गिरने नेशनल न्यूज़ चैनल से जुड़े रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि सीएमओ साहब की कुर्सी पर पहले भी इसी कलर का कवर रहता था आप हमारी न माने तो फोटो देख लें । फोटो उस समय की है जब डीएम साहब ने सीएमओ कार्यालय का निरीक्षण किया था। कानपुर के प्रबुद्ध वर्ग के बीच इन कुछ अति उत्साही पत्रकारों की कौवा कान ले गया कार्य संस्कृति की चर्चा चटखारे के साथ चल रही है।

बसपा ने बनाई चुनावी रणनीति,बूथ से सरकार तक!

» बिल्हौर में हुई बैठक, ज़िम्मेदारियाँ बांटी गईं

» कार्यकर्ताओं को मोर्चे पर उतरने के निर्देश

» जिलाध्यक्ष बोले बसपा से हर रोज जुड़ रहे सैकड़ों लोग

स्वराज इंडिया संवाददाता

बिल्हौर (कानपुर)। बहुजन समाज पार्टी ने आगामी चुनाव को लेकर कमर कस ली है। बिल्हौर के अलियापुर स्थित गेस्ट हाउस में बुधवार को हुई सेक्टर और बूथ कमेटियों की बैठक में संगठन को ज़मीनी स्तर पर मज़बूत करने की रणनीति तय की गई।

मुख्य मंडल प्रभारी अनिल पाल ने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियाँ सौंपीं और निर्देश दिया कि हर गली और हर बूथ पर बसपा की मज़बूत मौजूदगी दर्ज होनी चाहिए।जिलाध्यक्ष कुलदीप गौतम ने दावा किया कि लोग तेज़ी से पार्टी से जुड़ रहे हैं और बहुजन नीतियों में विश्वास जता रहे हैं।वहीं, बिल्हौर सीट से ताल ठोक रहे एडवोकेट विनय कुमार गौतम ने कहा कि बसपा ही सर्व समाज की सच्ची आवाज़ है।

बैठक में मंडल प्रभारी रामनारायण, वरिष्ठ नेता जीवनलाल भारती, प्रमोद गौतम, रमेश पाल, प्रेमचंद बौद्ध, पंडित दिनेश दुबे, सोबरन शास्त्री, हरमोहन सिंह, अफ़सर अली सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सम्पादकीय

व्यवस्थागत त्रास झेलते हरियाणा के स्कूल

हरियाणा के सरकारी स्कूल जिस बदहाली से गुजर रहे हैं उसका निष्कर्ष यही है कि ये स्कूल बीमार भविष्य के कारखाने साबित हो सकते हैं। हरियाणा के प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा हाल में किए गए युक्तीकरण के प्रयासों से राज्य में सार्वजनिक शिक्षा की निराशाजनक स्थिति ही उजागर हुई है। सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि राज्य में 487 सरकारी प्राथमिक विद्यालय बिना किसी शिक्षक के संचालित किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विडंबना यह है कि करीब 294 स्कूलों में कोई छात्र नामांकित नहीं है। निश्चय की छात्रों के मोहभंग के कारणों को समझना कठिन नहीं है। निश्चित रूप से यदि प्राथमिक शिक्षा की यह तस्वीर है तो माध्यमिक और उच्च शिक्षा की स्थिति और भी खराब हो सकती है। विडंबना यह भी है कि शिक्षा व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने की कवायद में शिक्षकों की बड़ी कमी के बावजूद पांच हजार से अधिक शिक्षकों के पद समाप्त हो गए हैं। हालांकि, छात्र-शिक्षक अनुपात 28ः1 प्रबंधनीय लग सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कहीं ज्यादा खराब है। लगभग 16,500 से अधिक टीजीटी और 11,341 पीजीटी शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। इतना ही नहीं राज्य के विश्वविद्यालय और कालेज भी शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। यहां तक कि सरकारी कॉलेजों में भी व्याख्याताओं के लगभग आधी पद खाली हैं। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि राज्य में योग्य बेरोजगारों की बड़ी संख्या के बावजूद ये पद खाली पड़े हैं। जो व्यवस्थागत खामियों की ओर ही इशारा करते हैं। विसंगति यह भी है कि बजटीय उपेक्षा ने समस्या को और बढ़ा दिया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पिछले साल एक संबंधित मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आवंटित बजट का समय रहते उपयोग न कर पाने के कारण शिक्षा निधि में 10,675 करोड़ रुपये वापस लौटने का उल्लेख किया था। जो शिक्षा विभाग की उदासीनता की ही तस्वीर ही उकेरता है।ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि एक ओर वित्तीय संसाधनों की कमी की बात कही जाती है और दूसरी ओर शिक्षा निधि में उपयोग न किए गए धन को लौटाने की बात सामने आ रही है। जाहिरा तौर पर यदि आवंटित धन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का दावा निरर्थक ही साबित होगा। कमोबेश शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाये जाते रहे हैं। कहा जा रहा है कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों के छात्रों का अंकगणितीय ज्ञान और साक्षरता का कौशल पंजाब व पड़ोसी राज्य हिमाचल से कमतर ही है। हाल में जारी वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट यानी एएसईआर 2024 एक गंभीर स्थिति को ही उजागर करती है। वार्षिक स्थिति रिपोर्ट में उजागर हुआ है कि ग्रामीण स्कूलों में कक्षा आठवीं तक के केवल 43.1 प्रतिशत छात्र ही गणित में भाग की गणनाएं कर सकते हैं। जो कि वर्ष 2022 में 49.5 प्रतिशत से कम ही है। जबकि दूसरी ओर पंजाब के स्कूलों के छात्र 58 फीसदी के साथ सबसे आगे हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश 44 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं दूसरी ओर पढ़ने का कौशल भी उतना ही चिंताजनक है। ऐसे में शिक्षा क्षेत्र गिरावट का ट्रेंड ही नजर आएगा। जाहिर है इससे छात्रों का ही नुकसान होगा। दरअसल, शिक्षा व्यवस्था की गंभीर खामियों को संबोधित करने की जरूरत है। निस्संदेह, सरकारी स्कूलों में समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों की ही अधिकता होती है। समाज के वंचित वर्ग के छात्र भी बड़ी संख्या में इन स्कूलों में दाखिले लेते हैं। उनकी पारिवारिक स्थिति कुछ ऐसी होती है कि अभिभावक की छात्रों के उन्नयन में आपेक्षित भूमिका नहीं हो पाती। ऐसे में शिक्षकों की जवाबदेही तय करने की जरूरत तो है ही, साथ ही शिक्षा विभाग को भी व्यवस्थागत विसंगतियों को दूर करने के लिये गंभीर प्रयास करने की जरूरत है। सरकार को भी शिक्षक-छात्र अनुपात को न्यायसंगत बनाने की दिशा में युद्ध स्तर पर प्रयास करने चाहिए। उन कारणों की भी पड़ताल हो जिनकी वजह से छात्रों का सरकारी स्कूलों में प्रदर्शन निराशाजनक बना हुआ है।

संसदीय सीटों के परिसीमन के यक्ष प्रश्न

प्रमोद जोशी

दक्षिणी राजनेताओं का तर्क है कि परिसीमन से राष्ट्रीय मंच पर उनकी आवाज़ और उपस्थिति कम होगी। उन्हें आर्थिक और सामाजिक-विकास का पुरस्कार मिलने के बजाय सज़ा मिलेगी। निस्संदेह, देश के विकास में क्षेत्रीय-असंतुलन के ऐतिहासिक-कारणों को समझते हुए भविष्य की संभावनाओं को भी देखना होगा।

केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से देश के राजनेताओं और विश्लेषकों के एक तबके ने दो-तीन बातों पर ज़ोर देना शुरू कर दिया है। वे कहते हैं कि भारत में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र विफल हो रहा है और यह भी कि लोकतंत्र का मतलब चुनाव जीतना भर नहीं होता। लोकतंत्र ही नहीं, संघवाद को भी खतरे में बताया जा रहा है। बीजेपी के हिंदू-राष्ट्रवाद की अतिशय केंद्रीय-सत्ता को लेकर भी उनकी आपत्तियां हैं।

इधर तमिलनाडु से हिंदी-साम्राज्यवाद को लेकर बहस फिर से शुरू हुई है, जिसमें संसदीय-सीटों के परिसीमन को लेकर आपत्तियां भी शामिल हैं। दक्षिण के नेताओं का तर्क है कि यदि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होगा, तब दक्षिण के राज्य नुकसान में रहेंगे, जबकि जनसंख्या-नियंत्रण में उनका योगदान उत्तर के राज्यों से बेहतर रहा है। उनका सुझाव है कि संसदीय परिसीमन में संघवाद के मूल्यों का अनुपालन होना चाहिए।परिसीमन से जुड़े इन्हीं सवालों को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 5 मार्च को चेन्नई में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा- तमिलनाडु अपने अधिकारों के लिए बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर है। परिसीमन का खतरा दक्षिणी राज्यों पर डैमोक्लीज़ की तलवार की तरह मंडरा रहा है। मानव विकास सूचकांक में अग्रणी तमिलनाडु के सामने गंभीर खतरा खड़ा है।उनका यह भी कहना है कि अभी तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं। परिसीमन की प्रक्रिया से इनकी संख्या घटकर 31 रह जाने की संभावना है। बात सिर्फ़ संख्या में कमी की नहीं है, यह हमारे अधिकारों का मामला है। स्टालिन के इस बयान के फौरन बाद गृहमंत्री अमित शाह ने कहा परिसीमन के बाद दक्षिणी राज्यों को 'एक भी सीट' नहीं गंवानी पड़ेगी। उन्होंने तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों की लंबे समय से चली आ रही इस आशंका को दूर करने का प्रयास किया कि यदि नवीनतम जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर परिसीमन किया गया तो संसद में उनका प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा।हालांकि इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन करना होगा, पर आज जो बातें हो रही हैं, वे कयासों और अटकलों पर आधारित हैं। संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 में प्रावधान है कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इसके विभाजन को फिर से समायोजित किया जाएगा। यह 'परिसीमन प्रक्रिया' संसद के एक अधिनियम के तहत गठित 'परिसीमन आयोग' द्वारा की जाती है।

इस तरह की कवायद 1951, 1961 और 1971 की जनगणना के बाद की गई थी। इसमें इन सदनों में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण भी शामिल है। वर्ष 1951, 1961 और 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में सीटों की संख्या 494, 522 और 543 तय की गई थी, जब जनसंख्या क्रमशः 36.1, 43.9 और 54.8 करोड़ थी। इसका मोटे तौर पर मतलब है कि प्रत्येक सीट पर औसतन क्रमशः 7.3, 8.4 और 10.1 लाख आबादी थी।जनसंख्या-नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए 1971 की जनगणना के बाद से इसे स्थिर रखा गया है ताकि अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों में सीटों की संख्या अधिक न हो। यह कार्य 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से पहले वर्ष 2000 तक के लिए किया गया था। फिर 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा 2026 तक बढ़ा दिया गया था। अभी जिस जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या तय है, वह 1971 की जनगणना के अनुसार है। 2026 के बाद पहली जनगणना के आधार पर इस संख्या को फिर से समायोजित किया जाएगा। अभी लगता नहीं कि 2026 के पहले वह जनगणना हो भी पाएगी या नहीं, जिसे 2021 में होना था। यह देखते हुए कि विधायिका में महिलाओं का आरक्षण भी जनगणना और परिसीमन से जुड़ा हुआ है, इसमें देरी दिक्कत पैदा करेगी।राज्यों में भी जनसंख्या वृद्धि में समतुल्यता के लिए सीटों की संख्या को 1971 की जनगणना के अनुरूप फ्रीज़ कर दिया गया है। 84वें संविधान संशोधन ने प्रावधान किया था कि परिसीमन की कवायद साल 2026 के बाद पहली जनगणना पर आधारित होगी। बहरहाल, पहले इस बात पर विचार करना होगा कि परिसीमन की नई प्रक्रिया में केवल राज्य की जनसंख्या का आनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा या नहीं। आनुपातिक संख्या पर नज़र डालें, तो तमिलनाडु की यह चिंता जायज़ है।

ग्लेशियरों पर संकट के बीच हमारी जिम्मेदारी

पर्यावरणीय जोखिम

वीरेन्द्र कुमार

ग्लेशियर पिघलना प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन मानवीय हस्तक्षेप जैसे जलविद्युत परियोजनाओं, निर्माण कार्यों और पर्यावरणीय असंतुलन ने इसे और बढ़ा दिया। ग्लेशियरों से हिमखंड टूटने की घटनाओं का जोखिम बढ़ा है, वहीं ग्लेशियल आउटबर्स्ट फ्लड के खतरे भी। इन संवेदनशील क्षेत्रों में गतिविधि न्यूनतम रखनी चाहिये। हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा ग्राम के पास हुई हिमस्खलन की घटना में बीआरओ के मजदूर दब गए थे, जिनमें से कुछ को बचा लिया गया, लेकिन कई की जानें नहीं बच सकीं।

दरअसल, हिमस्खलन की घटनाएं पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं, जिससे अचानक बाढ़ें आ रही हैं और सड़कों पर वाहन सवार सैलानियों की मौतें हो रही हैं। फरवरी, 2021 में उत्तराखंड की नीती घाटी में हिमस्खलन के कारण ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदियों में बाढ़ आई, जिससे व्यापक तबाही हुई। इस घटना के चलते वैश्विक स्तर पर हिमस्खलनों और ग्लेशियरों के संकट को लेकर चर्चा शुरू हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि ग्लेशियरों के पिघलने की प्रक्रिया में मानवीय गतिविधियों का भी योगदान है, जिससे इन घटनाओं की आवृत्ति बढ़ रही है। ग्लेशियरों का पिघलना प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन मानवीय हस्तक्षेप जैसे जलविद्युत परियोजनाओं, निर्माण कार्यों और पर्यावरणीय असंतुलन ने इसे और बढ़ा दिया। इसलिये, हमें इन संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।इक्कीसवीं सदी के प्रारंभ से हिमालयी ग्लेशियरों का पिघलना दुगनी दर से बढ़ गया है। वे हर साल आधे मीटर की मोटाई खो रहे हैं और कुछ क्षेत्रों में पीछे भी खिसक रहे हैं। गढ़वाल हिमालय में पिछले चार दशकों में औसतन 18 मीटर प्रति वर्ष ग्लेशियर पीछे खिसक रहे हैं। ग्लेशियरों के पिघलने की दर तापमान, बारिश, नमी, हवाओं की गति और

सूर्य की किरणों के परावर्तन पर निर्भर करती है। पिघलते ग्लेशियरों से उत्पन्न जल से गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी सदानीरा नदियों का अस्तित्व है, जो वर्षा के बिना भी बहती रहती हैं। यदि ग्लेशियरों का पिघलना जारी रहता है, तो इससे समुद्र स्तर 230 फुट तक बढ़ सकता है, जो वैश्विक जल संकट का कारण बन सकता है।नदियों में पानी की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, गंगा और यमुना के स्रोतों, गंगोत्री और यमुनोत्री के ग्लेशियरों को नैनीताल उच्च न्यायालय ने 20 मार्च, 2017 को एक आदेश में न्यायिक जीवित मानव का दर्जा दिया। हालांकि ग्लेशियर स्वयं मौसमी बदलाव और बढ़ते तापमान से काल-कवलित हो रहे हैं, लेकिन इनकी सतह जब सूर्य की किरणों को परावर्तित करती है, तो वे वातावरण संतुलन में भी मदद करती हैं। छोटे ग्लेशियर्स औसतन 70 से 100 मीटर तक मोटे होते हैं, जबकि बड़े ग्लेशियर्स 1.5 किमी तक मोटे हो सकते हैं।गतिक ग्लेशियर्स अपनी यात्रा के दौरान शिलाओं को तोड़ते हुए उन्हें उनके मूल स्थानों से दूर ले जाते हैं, जिससे हिमस्खलन के दौरान हिमखंडों के साथ बड़ी-बड़ी शिलाओं की भी बौछार होती है। जब ये हिमखंड और शिलाएं नदियों-नालों में गिरती हैं, तो कभी-कभी बहते पानी की राह रोक अस्थायी बांध बना देती हैं। इन बांधों के टूटने से अचानक बाढ़ों और तबाही का खतरा उत्पन्न हो सकता है। जिनके टूटने पर भारी मात्रा में पानी बहकर ये अचानक बाढ़ों का कारण बनती है, जिसे ग्लेशियल आउटबर्स्ट फ्लड कहा जाता है। ग्लेशियर्स प्रायः पहाड़ी निर्जन क्षेत्रों में होते हैं। अगर हम आर्थिक लाभ या मनोरंजन के लिए उनके नजदीक न जायें, तो शायद उनके टूटने या ग्लेशियर झीलों के अनायास टूटने का प्रभाव बस्तियों और संरचनाओं पर उतना भयंकर न होता। हालांकि, आज नंदादेवी बायोस्फीयर जैसे संरक्षित क्षेत्रों में भी विभिन्न प्रोजेक्ट, जैसे जल विद्युत परियोजनाएं, स्कीइंग रिसॉर्ट्स और वेडिंग डेस्टिनेशन जैसी गतिविधियों को लेकर प्रवेश किया जा रहा है, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई है।वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद, जीएसआई ने 2014-16 में एक विशेष अध्ययन किया, जिसमें उत्तराखंड में 486 ग्लेशियल झीलों की पहचान की गई, जिनमें से 13 अत्यधिक जोखिमपूर्ण हैं। इन झीलों में से 71 ऋषिगंगा और धौलीगंगा घाटियों के ऊपर स्थित हैं, जो भूकंप, बादल फटने या भूगर्भीय कारणों से विखंडित हो सकती हैं। यदि हिमखंडों के गिरने या बहने के रास्ते के भूभागों को कमजोर किया गया, तो फ्लैश फ्लड की संभावना बढ़ सकती है। ऐसे में, हमें ग्लेशियरों की अनदेखी करने की बजाय उनके संवेदनशील क्षेत्रों जैसे नंदादेवी बायोस्फीयर और गंगोत्री, केदारनाथ के आसपास के संरक्षित क्षेत्रों को पारिस्थितिकीय असंतुलन से बचाने की नीति अपनानी चाहिए। ग्लेशियरों के नीचे पहाड़ी दरारों में पानी जमना और बर्फ का पिघलना भी एक सतत प्रक्रिया है, जो पहाड़ों को कमजोर करती है।

करोड़ों खर्च और नतीजा शून्य आरआरसी सेंटरों की आड़ में बड़े घोटाले की बू

शिवांक अग्निहोत्री/ स्वराज इंडिया

» करोड़ों की योजना, लेकिन बिना उपयोग के खड़े सेंटर

» ताले, वीरानी और सन्नाटा आर आर सी केंद्रों की सच्चाई

» निर्माण में घोटाले के संकेत नई दीवारें भी दरकने लगीं

» 30.5 करोड़ खर्च पर कोई जवाबदेही नहीं?

कानपुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छता अभियान के तहत कानपुर जिले की 305 ग्राम पंचायतों में आर आर सी सेंटर बनवाने के लिए प्रत्येक पंचायत को ?10 लाख का बजट आवंटित किया। इस हिसाब से कुल बजट ?30.5 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जिनका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में कचरे का वैज्ञानिक, व्यवस्थित और पर्यावरण के अनुकूल निस्तारण। यह केंद्र वाकई में ज़मीन पर बने हैं इमारतें खड़ी हैं, कुछ जगहों पर रंग-रोगन भी किया गया है, लेकिन जब स्वराज इंडिया की टीम ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया, तो सामने आई हकीकत चौंकाने वाली थी। ज़्यादातर केंद्रों पर ताले लटके थे, अंदर कोई मशीनरी, कोई सफाई कर्मी या प्रबंधन व्यवस्था मौजूद नहीं थी। यानी पैसा खर्च तो हुआ, ढांचा खड़ा भी हुआ, लेकिन वह ढांचा व्यवहारिक उपयोग से कोसों दूर है।

बने तो हैं सेंटर, लेकिन वीरानी और सन्नाटा इनकी पहचान बन चुकी है

गांवों में जहाँ ये केंद्र बने हैं, वहां के लोगों से जब बात की गई तो साफ़ तौर पर उन्होंने कहा "हमें तो पता भी नहीं कि ये सेंटर क्यों बने हैं और इसमें क्या होता है।" कुछ लोगों ने बताया कि इमारत बनकर कई महीनों से बंद पड़ी है, कभी-कभार कोई झांकने तक नहीं आता। कहीं ये सेंटर गोदाम बने हुए हैं, कहीं बच्चों का अड्डा, और कुछ जगह तो इतनी बदहाल हालत में हैं कि गांव के लोग उन्हें भूतिया घर कहने लगे हैं। कुछ केंद्रों में खिड़कियाँ गायब हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं और आसपास झाड़ियाँ उग आई हैं। न तो इनका उद्घाटन ठीक से हुआ, न रखरखाव, न ही कोई सफाई प्रक्रिया शुरू की गई। सरकार की करोड़ों की ये योजनाएं सिर्फ ढांचा बनाकर छोड़ देने की मिसाल बन गई हैं।

घटिया निर्माण की खुली पोल नई इमारतों की दीवारें दरकने लगीं

स्वराज इंडिया की ग्राउंड टीम ने पाया कि जिन सेंटरों पर 10 लाख रुपये खर्च किए गए, उनकी इमारतों की हालत बेहद खराब है। कई स्थानों पर दीवारें दरक चुकी हैं, छतों में दरारें पड़ गई हैं, और प्लास्टर जगह-जगह से उखड़ रहा है। कहीं सीढ़ियाँ अधूरी हैं, तो कहीं फ्लोरिंग ही नहीं डली। कुछ सेंटरों की दीवारों में नमी, सीलन और रंग की परत उतरती दिखी। यह साफ संकेत है कि निर्माण कार्य में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। स्थानीय सूत्र बताते हैं कि सस्ती सामग्री, जल्दबाज़ी में ठेकेदारी, और बिना गुणवत्ता जांच के निर्माण इस बदहाली की बड़ी वजह है। यदि अभी इनकी मरम्मत नहीं की गई, तो ये केंद्र कुछ ही महीनों में पूरी तरह जर्जर होकर ध्वस्त हो सकते हैं।

30.5 करोड़ का सवाल जवाबदेही किसकी और जांच कब?

जब एक भी केंद्र अपने उद्देश्य के अनुरूप उपयोग में नहीं है, तो ये सवाल उठना लाज़मी है कि 305 पंचायतों में खर्च किए गए ?30.5 करोड़ रुपये आखिर गए कहां? क्या इन पर कोई ऑडिट हुआ? क्या किसी अधिकारी ने जाकर देखा कि वहाँ कोई गतिविधि हो रही है या नहीं? ज़मीनी सच्चाई यह है कि सरकारी बजट का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया है, और किसी को इसकी चिंता नहीं। यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि एक संभावित वित्तीय घोटाले की शुरुआत है। यदि पूरे प्रदेश में यही हाल है, तो ये आंकड़ा सैकड़ों करोड़ रुपये के नुकसान तक पहुंच सकता है। ज़रूरत है एक उच्चस्तरीय स्वतंत्र जांच की, और उन अधिकारियों व ठेकेदारों को जवाबदेह बनाने की जिनकी वजह से करोड़ों की योजनाएं जनता के किसी काम नहीं आ रही हैं।

नाले की आड़ में मिट्टी की लूट! प्रधान ने बेचीं सैकड़ों ट्रॉली मिट्टी

मौके पर जांच करते अधिकारी

उक्त प्लाट धारक को बेची गई मिट्टी

» ग्रामीणों की शिकायत पर हरकत में आया प्रशासन, राजस्व टीम ने की जांच

» जेसीबी से की गई खुदाई में आरआरसी सेंटर का प्रवेश द्वार की इंटरलॉकिंग क्षतिग्रस्त

इसी जगह से की गई मिट्टी की अवैध खुदाई

आरोपी प्रधान राजेश कुमार

प्रमुख संवाददाता दैनिक स्वराज इंडिया

कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के चौबेपुर ब्लॉक की राय गोपालपुर ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान राजेश कुमार पर भारी अनियमितताओं और सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों के अनुसार, प्रधान ने नाले की खुदाई के नाम पर गांव की ज़मीन से सैकड़ों ट्रॉली मिट्टी की खुदाई करवा दी, जिसे गांव में ही एक निजी प्लॉट धारक को बेच दिया गया। जब इस अवैध गतिविधि को लेकर ग्रामीणों ने प्रधान से जवाब तलब किया तो उन्होंने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि उपरोक्त अधिकारियों से नाले की खुदाई का आदेश प्राप्त है। लेकिन जब ग्रामीणों ने उस आदेश की लिखित प्रति मांगी, तो प्रधान कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। इससे ग्रामीणों का शक और गहराया कि कहीं यह पूरा काम केवल पैसे कमाने के लिए तो नहीं किया जा रहा।

ग्रामीणों ने इस विषय में शिकायत करते हुए खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) चौबेपुर से संपर्क किया। मामला गंभीर प्रतीत होने पर ब्लॉक प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए राजस्व विभाग की टीम को भेजा। टीम ने मौके पर पहुंचकर उन सभी स्थानों की जांच की जहां से मिट्टी का खनन हुआ था। जांच के दौरान यह बात भी सामने आई कि नाले की खुदाई संबंधी कोई लिखित अनुमति या योजना पास नहीं की गई थी।

इस अवैध खुदाई का असर केवल ज़मीन तक सीमित नहीं रहा। जब ग्राम प्रधान द्वारा जेसीबी मशीन का उपयोग कर खुदाई करवाई गई, तो मिट्टी उठाने के दौरान गांव में बने आरआरसी सेंटर (कचरा संग्रह केंद्र) के प्रवेश द्वार की इंटरलॉकिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। यह सेंटर ग्रामीण स्वच्छता मिशन के तहत लाखों की लागत से बनाया गया था, लेकिन अब वह गंदगी, टूट-फूट और लापरवाही का शिकार हो गया है।

गांव में अब जनता में आक्रोश है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब कोई लिखित आदेश नहीं था तो प्रधान को यह अधिकार किसने दिया कि वह जेसीबी लगाकर मिट्टी खुदवाए और उसे बेच भी दे? ग्रामीणों का कहना है कि यह सीधा-सीधा घोटाले और अवैध लाभ कमाने का प्रयास है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, दोषी पाए जाने पर प्रधान को पद से हटाया जाए और नुकसान की भरपाई सरकारी खजाने में वापस कराई जाए। साथ ही जिन सरकारी ढांचों को नुकसान पहुंचाया गया है, उनकी मरम्मत की जिम्मेदारी भी प्रधान पर तय हो।

यह पूरा मामला न केवल एक गांव की समस्या है, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे स्थानीय स्तर पर सरकारी योजनाओं की आड़ में पैसे की लूट की जा रही है, और कैसे जनप्रतिनिधि जनसेवा की जगह निजी फायदे को प्राथमिकता दे रहे हैं।

कानपुर देहात में जल संरक्षण की बड़ी सफलता, छह ब्लॉक सुरक्षित श्रेणी में पहुंचे

» 2023 में सात ब्लॉक थे सेमी क्रिटिकल, अब तीन ब्लॉक सुरक्षित कैटगरी में शामिल

» 81343 हेक्टेयर जल रिचार्ज, अमृत सरोवर से लेकर रेनवाटर हार्वेस्टिंग तक का असर

» जल संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। जल संरक्षण को लेकर किए गए विशेष प्रयासों का असर अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश गतिशील भूजल संसाधन रिपोर्ट 2024 के अनुसार, जिले के 10 में से 6 विकासखंडों का भूजल स्तर अब सुरक्षित श्रेणी में दर्ज किया गया है। वर्ष 2023 की रिपोर्ट में जहां 7 विकासखंड सेमी क्रिटिकल स्थिति में थे, वहीं इस बार की रिपोर्ट में झींझक, मैथा और रसूलाबाद जैसे ब्लॉक सुरक्षित श्रेणी में आ गए

हैं। पहले से सुरक्षित माने जा रहे राजपुर, संदलपुर और अमरौधा को मिलाकर अब कुल छह विकासखंड इस कैटेगरी में पहुंच गए हैं।

यह बदलाव, जिलाधिकारी आलोक सिंह और मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा किए गए ठोस प्रयासों का प्रतिफल है।

जागरूकता, योजनाएं और रिचार्ज प्रयास बने सफलता की कुंजी

मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन ने बताया कि जल संरक्षण को लेकर सभी संबंधित विभागों को दैनिक मॉनिटरिंग के साथ योजनाएं लागू करने को कहा गया था। चेकडैम, खेत तालाब, अमृत सरोवर, रेनवाटर हार्वेस्टिंग, रीचार्ज शाफ्ट, नून नदी पुनर्जीवन, और ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई जैसे उपायों को ज़मीनी स्तर पर लागू किया गया। साथ ही, फैक्ट्रियों में वाटर रिसाइकलिंग और जन भागीदारी के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाए गए। इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप अब तक 81343.31 हेक्टेयर क्षेत्र में जल पुनर्भरण (रिचार्ज) किया गया है। 70% से कम जल उपयोग की स्थिति तक पहुंचना एक महत्वपूर्ण संकेत है कि जनपद अब जल संकट से उबरने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट में कानपुर देहात को सबसे अधिक सुधार वाले जिलों में शामिल किया गया है, जो आने वाले समय में जल सुरक्षा की स्थायी नींव रखने का संकेत है।

18 बार निर्देश के बाद भी नहीं बना 100 मी. खड़ंजा, डीपीआरओ ने दी सख्त चेतावनी

» थाने के सामने मोहल्ले के खस्ताहाल रास्ते को लेकर ग्रामीणों ने डीएम से लेकर सीएम तक लगाई गुहार

» अबकी बार डीपीआरओ ने दी चेतावनी बुलाए जाएंगे सचिव-प्रधान, नहीं हुआ कार्य तो होगी कार्रवाई

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। अमरौधा ब्लॉक के भोगनीपुर थाने के सामने स्थित मोहल्ले में 100 मीटर खड़ंजा निर्माण को लेकर जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) विकास पटेल ने 18वीं बार सचिव और ग्राम प्रधान को निर्देश जारी किए हैं। बावजूद इसके अब तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है।

ग्रामीणों ने टूटी सड़क की शिकायत पहले खंड विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और जिलाधिकारी तक की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने पांच बार उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दो बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में जाकर गुहार लगाई, फिर भी खड़ंजा नहीं बन पाया।

मंगलवार को मोहल्लेवासियों ने एक बार फिर डीपीआरओ से मुलाकात कर लिखित में आवेदन दिया। इस पर विकास पटेल ने कहा कि बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी के आगमन पर सचिव और प्रधान को बुलाकर कार्य शुरू कराया जाएगा। यदि इसके बाद भी खड़ंजा निर्माण नहीं होता, तो संबंधित जिम्मेदारों पर विभागीय कार्रवाई तय मानी जाएगी। डीपीआरओ ने बताया कि इस बाबत मुख्य विकास अधिकारी को पत्र भेजा जा चुका है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। संपादकः अनूप कुमार RNI No.: UPHIN/2023/86769 | Email: swarajindia2023@gmail.com | Mob: 7800009853, | Website: www.swarajindianews.com | (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

नकली डामर फैक्ट्री पर प्रशासन का छापा, प्लांट और मशीनरी सीज

जिलाधिकारी के निर्देश पर बनी टीम ने की बड़ी कार्रवाई, बिना लाइसेंस और मानकों के चल रहा था अवैध निर्माण

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देश पर प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तहसील सिकन्दरा के ग्राम खोजाफूल में चल रहे अवैध नकली डामर निर्माण प्लांट पर छापा मारकर उसे सीज कर दिया। यह कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा गठित विशेष टीम जिसमें उपायुक्त उद्योग मोहम्मद सउद, इंजीनियर साहिब आलम, एई आरईडी योगेन्द्र शर्मा और नायब तहसीलदार रवीन्द्र मिश्र शामिल थे द्वारा की गई।

टीम को मौके से भारी मात्रा में नकली डामर की सामग्री, कच्चा तेल, रसायन, मिक्सिंग उपकरण, और निर्माण मशीनें बरामद हुईं। जांच में यह भी सामने आया कि यह प्लांट बिना वैध लाइसेंस, पर्यावरणीय स्वीकृति, और किसी सुरक्षा मानक के पूरी तरह अवैध रूप से संचालित हो रहा था।प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से संपूर्ण निर्माण सामग्री और मशीनरी को सीज कर दिया है। साथ ही, संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ विधिक कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी गई है।

जिलाधिकारी आलोक सिंह ने स्पष्ट कहा कि जिले में किसी भी प्रकार की अवैध, मानकविहीन और जनविरोधी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुशासन, पारदर्शिता और विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अवैध कारोबारों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। साथ ही उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे इस प्रकार की किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना प्रशासन को तत्काल दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

ग्रामीण स्कूलों के विलय पर बवाल: शिक्षक संगठनों और छात्रों का जोरदार विरोध

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश में कम छात्र संख्या वाले परिषदीय स्कूलों को बंद या मर्ज करने के फैसले का जोरदार विरोध शुरू हो गया है। अब न सिर्फ शिक्षक संगठन, बल्कि प्रतियोगी छात्र भी इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर चुके हैं। बुधवार को सेव विलेज स्कूल के नाम से सोशल मीडिया पर व्यापक अभियान चलाया गया।इस निर्णय के तहत प्रदेश के उन स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है जहां छात्र संख्या 50 से कम है। अकेले कानपुर देहात जिले में ऐसे 700 से अधिक स्कूल हैं, जिनकी आसपास एक किमी के दायरे में कोई अन्य विद्यालय नहीं है। ग्रामीण इलाकों में सड़कें भी उपयुक्त नहीं हैं, जिससे छोटे बच्चों के लिए दो-तीन किमी दूर स्थित नए स्कूल तक पहुंचना कठिन होगा। इससे गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा बाधित होने की आशंका है।

» सेव विलेज स्कूल अभियान तेज, शिक्षक नेताओं ने चेताया—आंदोलन और न्यायिक लड़ाई को तैयार

» भर्ती की उम्मीदों को झटका, अभ्यर्थी बोले—स्कूल मर्जर से हजारों पद खत्म होंगे

शिक्षक संगठनों ने दी आंदोलन की चेतावनी

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने इस फैसले को गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम हर बच्चे को उसके निकट शिक्षा का अधिकार देता है, लेकिन यह आदेश उस मूल भावना का उल्लंघन है।

उन्होंने सरकार को चेताया कि यदि आदेश वापस नहीं लिया गया तो प्रदेशभर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो कोर्ट का रुख भी किया जाएगा।

अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने इस निर्णय को शिक्षा के निजीकरण की ओर बढ़ता कदम करार दिया है। उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के अध्यक्ष योगेश त्यागी ने भी इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि इससे गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा।

वहीं प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि अगर कक्षा 8 तक के 25,000 से ज्यादा स्कूलों को मर्ज किया गया तो हजारों शिक्षकों के पद खत्म हो जाएंगे, जिससे भविष्य की भर्तियों पर बड़ा असर पड़ेगा। डीएलएड और बीएड धारक अभ्यर्थियों ने भी इसे शिक्षा व्यवस्था के लिए घातक बताते हुए सरकार से आदेश वापस लेने की मांग की है।

अघोषित 'प्रतिबंध राज' में फंस गई अयोध्या!

स्वराज इंडिया संवाददाता

अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या को वैश्विक धार्मिक राजधानी बनाने के सपने में जुटे हैं, लेकिन ज़मीन पर पुलिस और नगर निगम की कार्यशैली इस सपने में कील ठोक रही है। रामनगरी की सड़कों पर इन दिनों श्रद्धालु ही नहीं, स्थानीय व्यापारी भी प्रशासन की अघोषित बंदिशों से त्रस्त हैं। नयाघाट से रामजन्मभूमि तक दर्शन और व्यापार के रास्ते में पुलिसिया बेरोकटोक अड़चनें, अव्यवस्थित पार्किंग और 'ठेकेदारी व्यवस्था' ने श्रद्धा के साथ कारोबार को भी ठप कर दिया है।

» कई जगहों पर बैरिकेडिंग और बंदिशें से श्रद्धालु परेशान, व्यापार तबाह

» नगर निगम और यातायात प्रबंधन की मनमानी से स्थानीय लोग अधिक प्रभावित

छपिया, कटरा, परशुरामपुर और सरयू के पार के गांवों से आने वाले श्रद्धालु अब अयोध्या तक पहुंचने से पहले ही थक-हार जाते हैं। वजह है - नयाघाट से प्रवेश पर मौखिक प्रतिबंध, दो किलोमीटर दूर की पार्किंग और उससे भी ज्यादा - धूप में 10 किलोमीटर तक पैदल चलने की मजबूरी।

पहले जहां भक्त दर्शन के साथ-साथ खरीदारी कर रामनगरी की अर्थव्यवस्था को गति देते थे,

अब वही श्रद्धालु पीछे हट रहे हैं। दुकानदार बेहाल हैं, कारोबार ठप है, लेकिन पुलिस और नगर निगम एक रटी-रटाई दलील दे रहे हैं जाम न लगे इसलिए ये सब किया गया है।

असल सवाल यह हैं....

-जब कोई मेला नहीं, कोई आयोजन नहीं तो फिर ये 'अघोषित प्रतिबंध' क्यों?

-क्या ये श्रद्धालुओं की सुविधा है या सुनियोजित कष्ट? स्थानीय लोगों की मानें तो दो लेन वाहनों के लिए और दो लेन पैदल श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाए तो न सिर्फ यातायात सुगम हो जाएगा बल्कि व्यापार को फिर से संजीवनी मिल सकती है।

श्रद्धालु भी परेशान हैं, दुकानदार टूट चुके हैं।

और नगर निगम-यातायात विभाग की जोड़ी कान में रुई डाल कर बैठी है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की अयोध्या को विश्वमंच पर प्रतिष्ठित करने की मंशा पर सवाल इसलिए नहीं हैं कि नीयत गलत है,

बल्कि इसलिए हैं कि नीचे के भ्रष्ट-प्रशासनिक ढांचे ने इस मंशा को गिरवी रख दिया है। यह अयोध्या अब श्रद्धा का नहीं, डर और धोखे का शहर बनता जा रहा है।

कानून भूली पुलिस...और किशोरी ने जिन्दगी से मानी हार

» थानाध्यक्ष की कार्यशैली फिर सवालों के घेरे में

थाने में दफ़न हुआ कानून... और जल गई एक बेटी!

बेटी की चीख से भी नहीं जागी पुलिस... अब जांच का नाटक!

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या।रामजन्म भूमि क्षेत्र में खुद को आग लगाने वाली 17 वर्षीय किशोरी ने बुधवार सुबह मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक घटना के बाद सवाल अब सिर्फ मौत पर नहीं, बल्कि पुलिस की लापरवाह कार्यशैली पर भी उठ रहे हैं। नियमों का खुला उल्लंघन कर नाबालिग को सीधे परिजनों को सौंपने वाली पुलिस अब कटघरे में है।

पुलिस का दावा है कि परिजनों की इच्छा पर कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन कानून के मुताबिक पुलिस को किशोरी को वन स्टॉप सेंटर भेजकर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था। न कोई केस, न काउंसलिंग, न मानसिक स्थिति का मूल्यांकन—सब कुछ दरकिनार कर दिया गया और आखिरकार किशोरी की जीवनलीला समाप्त हो गई।

सीओ आशुतोष तिवारी खुद मानते हैं कि प्रक्रियागत चूक हुई है और जांच की जाएगी। किशोरी के मोबाइल संवादों की सीडीआर खंगालने की बात कही जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जांच का दायरा पुलिस की लापरवाही तक भी जाएगा?

इनायतनगर से रामजन्मभूमि तक... थानाध्यक्ष अभिमन्यु शुक्ला की कार्यशैली सवालों में

पूर्व में इनायतनगर थाने पर भी पोक्सो एक्ट में नियमों के उल्लंघन को लेकर उनकी कार्यशैली पर सवाल उठे थे। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन ने इसकी शिकायत सीधे एसएसपी से की थी। अब रामजन्मभूमि थाने पर भी वही लापरवाही दोहराई गई।

बाल कल्याण समिति ने की कार्रवाई की मांग

सीडब्लूसी के अध्यक्ष सर्वेश अवस्थी ने एसएसपी को पत्र भेजकर नियमों के उल्लंघन की जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा, 卐किशोरी को परिजनों को सौंपना नियमों के विरुद्ध था। ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई न हुई तो बाल हितों की रक्षा नामुमकिन है।

जब कानून रक्षक ही कानून की राह से भटकें, तो मासूमों की जान पर बन आती है। एक चूक ने एक जान ले ली। क्या अब कोई ज़िम्मेदारी तय होगी, या फिर यह मौत भी पुलिस डायरी में एक 'औपचारिक केस नंबर' बनकर रह जाएगी?

बिल्हौर में एसडीएम ज्वाला प्रसाद ने कार्यभार संभाला

» बोले आम आदमी की शिकायतों का निस्तारण पहली प्राथमिकता

» अधिकारियों कर्मचारियों के बीच समन्वय बनाकर करेंगे काम

» ग्रामीण परिवेश को समझते हैं बेहतर ढंग से

रिज़वान कुरैशी/स्वराज इंडिया

बिल्हौर(कानपुर)। नवनियुक्त उपजिलाधिकारी बिल्हौर ज्वाला प्रसाद ने कहा कि आम आदमी की शिकायतों का निस्तारण और लंबित वादों का निपटारा करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। वह तहसील कर्मियों के कार्यों को निर्धारित समय में पूरा कराने का प्रयास करेंगे। अधीनस्थ अधिकारियों - कर्मचारियों के साथ समन्वय बनाकर काम करने की कोशिश करेंगे।

एसडीएम ज्वाला प्रसाद

तीन साल की तैनाती में बनाई अलग पहचान

करीब तीन साल तक बिल्हौर एसडीएम रही रश्मि लाम्बा ने बिल्हौर में अपना सख्त लेकिन संवेदनशील अफ़सर वाला चेहरा दिखाया। जनसुनवाई से लेकर अतिक्रमण हटाने तक उन्होंने मौके पर पहुंचकर काम किया। कई बार विरोध और धरनों का भी सामना किया, लेकिन फैसले ज़मीन पर उतरे।राजस्व विवादों और ग्रामीण समस्याओं पर उनका रवैया साफ और निडर रहा। वह राजनीतिक रूप से दोनों ही खेमों को साधे रहीं। जिसके कारण कई मोर्चों पर परेशान होने के बावजूद पराजित नहीं हुईं। रश्मि लाम्बा के छुट्टी पर जाने के बाद बुधवार को नए एसडीएम ज्वाला प्रसाद ने चार्ज संभाल लिया है।

नए एसडीएम से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की उम्मीद जागी

बिल्हौर। एसडीएम बिल्हौर शैक्षिक पृष्ठभूमि से जुड़े हैं। प्रशासनिक सेवा में आने से पूर्व वह एक इंटर कॉलेज में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक थे। उनकी पत्नी भी बेसिक शिक्षा विभाग में टीचर हैं। बिल्हौर में तैनाती से पहले उनके पास अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय और एसडीएम न्यायिक नरवल का पद था। जिस पर उन्होंने कुशलतापूर्वक कार्य किया। उनके बिल्हौर आने से शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद जागी है। कई सरकारी स्कूल आज भी रास्ते की समस्या से जूझ रहे हैं। जिनमें प्रशासन की थोड़ी सी पहल से समस्या दूर हो सकती है।

तय की जाएगी लापरवाह कर्मचारियों की जिम्मेदारी

बिल्हौर। अव्यवस्थाओं से जूझ रही बिल्हौर तहसील को पटरी पर लाने के बाबत उन्होंने कहा कि संज्ञान में आया है कि कुछ कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी से जी चुरा रहे है । जिससे आम आदमी को समस्याएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मचारी अपने रवैये में सुधार कर लें अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। कहा कि प्रत्येक कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। किसी को मनमाने ढंग से काम करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

सामाजिक विज्ञान का शिक्षक होने के नाते है बढ़िया सामाजिक ज्ञान

बिल्हौर। बिल्हौर के एसडीएम प्रशासनिक सेवा में आने से पहले टीजीटी सामाजिक विज्ञान के शिक्षक थे। उन्हें आगरा में पहली तैनाती मिली थी। 2018 बैच के पीसीएस अफसर ज्वाला प्रसाद का व्यक्तित्व बेहद सादगी भरा है। शायद उन्हें यह व्यक्तित्व शिक्षक की नौकरी के दौरान मिला। आज भी वह सीखने सिखाने की प्रक्रिया को अपने जीवन से जोड़े हुए हैं। वह जीवन में कोशिश करना कभी नहीं भूलते।

उपजिलाधिकारी बुधवार को बिल्हौर तहसील में कार्यभार ग्रहण करने के बाद स्वराज इंडिया अख़बार से खास बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, जमीनों की पैमाईश और गांव – गली की छोटी – छोटी समस्याएं लेकर आने वाले आम फरियादियों को राहत दिलाने के हर संभव प्रयास करेंगे। मूलरूप से आजमगढ़ के निवासी श्री प्रसाद बेहद सरल स्वभाव के हैं। प्रशासनिक सेवा में आने से पूर्व वह शिक्षक थे। शायद यही वजह है जो उन्हें आम आदमी से आसानी से जोड़ देती है। उन्होंने कहा कि वह आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि वह स्वयं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं द्य इसलिए उन्हें गांवों की समस्याओं की बेहतर समझ है। कहा कि गांव के लोग बड़ी उम्मीदों के साथ दूर–दूर से अधिकारियों के पास आते हैं। हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बार और बेंच के बीच आए दिन होने वाले मनमुटाव और कार्य बाधित होने के मुद्दे से वह कैसे जूझेंगे? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रतिमाह बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। ताकि उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। कहा कि आम आदमी अपनी बात बेहतर ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाता है। इस कार्य में वकील अहम भूमिका निभाते हैं। कहा कि जब लोगों से नियमित बातचीत होगी तो उम्मीद है कि सामंजस्य बना रहेगा।

इकतरफा प्यार में पागल प्रेमी ने की थी नवविवाहिता की हत्या, गिरफ्तार

स्वराज इंडिया संवाददाता

बिल्हौर(कानपुर)। बिल्हौर सर्किल के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बसेन गांव से तीन सप्ताह पहले विदा होकर गई नवविवाहिता की हत्या उसके प्रेमी ने की थी। वह चार दिन पहले ही मायके आई थी। और पहले से घात लगाए बैठा उसके एक तरफा प्यार में पागल प्रेमी ने घटना को अंजाम दे डाला।

» पिता बोला कह रहा था कि कहीं और शादी की तो मार डालेगा

»पोस्टमार्टम में नहीं हो पाई सामूहिक दुराचार की पुष्टि

»चौबेपुर हत्याकांड फॉलोअप

FOLLOW UP

मृतका के पिता की तहरीर पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट से इसका खुलासा हो गया है। पुलिस हत्यारोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। जिससे पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामूहिक दुराचार की पुष्टि नहीं हो पाई है। मृतका का बिसरा सुरक्षित कर लिया गया है।

पुलिस में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में मृतका के पिता ने कहा है कि गांव का दबंग सरोज राठौर पुत्र स्व सियाराम जबरन उसकी बेटी संध्या से एकतरफा प्यार करता था और उसके साथ उससे जबरन शादी करने हेतु उसे परेशान करता था।

जिसकी शिकायत जैसे ही उसकी बेटी ने मुझसे की तो मैंने तुरन्त सरोज के घर जाकर उससे कहा कि तुम आखिर मेरी लडकी को क्यों परेशान करते हो। जिस पर सरोज राठौर ने धमकी देते हुए मुझसे कहा कि साले कान खोल कर सुन ले यदि संध्या की शादी कहीं और जगह की तो मैं संध्या को जिंदा नही छोड़ूंगा। जिस पर डर के मारे मैं कही सरोज की शिकायत नहीं कर सका और दौड़ धूपकर मैने 26 मई 2025 को अपनी लड़की संध्या की कन्नौज की तरफ शादी करके विदा कर दिया। जैसे ही 15 मई को संध्या को ससुराल से विदा कराकर लाया उसी रात सरोज राठौर लड़की को किसी प्रकार चुपचाप घर से बाहर ले गया और कुछ ही दूरी पर एक पेड़ पर साड़ी से फांसी लगाकर लटका कर उसकी हत्या करके मौके से भाग गया। पुलिस मामले में हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है ।

इजरायल के सरोका अस्पताल पर ईरान का मिसाइल अटैक

इजरायल ने भी ईरान में यूरोनियम सेंट्रीफ्यूज व मिसाइल बनाने वाली इकाइयों पर किया हमला

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो/एजेंसी

नई दिल्ली। इजरायल और ईरान के बीच जंग सातवें दिन भी जारी है। ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। वहीं इजरायल ने भी ईरान में यूरोनियम सेंट्रीफ्यूज और मिसाइल बनाने वाली इकाइयों पर हमला बोला। मिडिल ईस्ट धीरे-धीरे एक बड़े जंग की ओर बढ़ रहा है। इजरायल और ईरान के बीच जंग सातवें दिन भी जारी है। ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। वहीं इजरायल ने भी ईरान में यूरोनियम सेंट्रीफ्यूज और मिसाइल बनाने वाली इकाइयों पर हमला बोला। इजरायल के हमले में ईरान में अब तक 639 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अमेरिका भी इस जंग में कूद सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अंतिम आदेश का इंतजार किया जा रहा है।

अमेरिका का हस्तक्षेप ईरान-इजरायल युद्ध को और भड़काएगा-क्रेमलिन : क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि ईरान-इज़राइल संघर्ष में अमेरिका की ओर से किया गया कोई भी हस्तक्षेप इस तनाव को और ज्यादा बढ़ा देगा। इज़रायल का कहना है कि ईरान के शीर्ष सैन्य नेताओं, परमाणु वैज्ञानिकों, यूरेनियम संवर्धन स्थलों और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर उसका व्यापक हमला रक्षा के लिए उठाया गया कदम है। क्योंकि ईरान इजरायल को नष्ट करने के लिए परमाणु बम बना रहा है।

ईरान में घुसे इजरायल के 40 विमान, मचाई तबाही : इजरायल रक्षा बलों (ढ्ढष्ठस्न) ने ईरान के अराक परमाणु रिएक्टर को भी निशाना बनाया है। इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि खुफिया विभाग के सटीक इनपुट के बाद हमारे 40 लड़ाकू विमानों ने 100 से ज्यादा गोला-बारूद के साथ तेहरान समेत अन्य इलाकों में ईरान के दर्जनों सैन्य ठिकानों पर अटैक किया।

कीमत चुकानी होगी : नेतन्याहू

इजरायल के अस्पताल और अन्य इलाकों में ईरान के ताजा हमले के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ी चेतावनी दी है। नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा-ईरान के आतंकवादी तानाशाह (अयातुल्ला अली खामेनेई) के सैनिकों ने सरोका अस्पताल और नागरिक आबादी पर मिसाइलें दागी हैं। उन्हें इसकी पूरी कीमत चुकानी होगी।

ट्रंप को दिया धन्यवाद

इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की और समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हम लगातार अमेरिका से बात कर रहे हैं। हमने राज्य के लिए दो खतरों को खत्म करने के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत की है। हमने तेहरान के स्पेस पर कब्जा कर लिया है।

जंग में अब अमेरिका भी कूदेगा

ट्रंप ने अटैक प्लान को दी मंजूरी, बोले-मैं कुछ भी कर सकता हूं

नई दिल्ली। ईरान-इजरायल जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान डील करना चाहता है। इस बीच ये खबर भी है कि इस जंग में अब अमेरिका भी कूदने जा रहा है। ट्रंप ने इजरायल और ईरान के दरमियान बढ़ते तनाव पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि उनके पास हर मसले का हल मौजूद है, मगर नतीजा क्या होगा, ये अभी कहा नहीं जा सकता है। ट्रंप ने ईरान पर हमले का आदेश देने के सवाल कहा, मेरे पास हर चीज का प्लान है...कुछ भी हो सकता है।

इस बयान से साफजाहिर होता है कि हाल ही में ईरान के साथ नाकाम रही बातचीत और जंग में सुलग रहे मिडिल ईस्ट ने उन्हें परेशान कर रखा है। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने उनके साथ एक

बेहतरीन सौदा करने का मौका गंवा दिया। उन्होंने कहा, उन्हें वो सौदा करना चाहिए था। मेरे पास उनके लिए एक शानदार डील थी। ट्रंप ने ये भी बताया कि ईरान अब बातचीत करना चाहता है और व्हाइट हाउस आने की ख्वाहिश रखता है, मगर वो हालात के मुताबिक ही कोई फैसला लेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दुनिया को इस बात पर अटकलें लगाने पर मजबूर कर दिया है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका इजरायल की ओर से ईरानी न्यूक्लियर साइट पर बम बरसाने में शामिल होगा।

व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने यह कहने से इनकार कर दिया कि क्या उन्होंने इजरायल के अभियान में शामिल होने के बारे में कोई फैसला किया है। उन्होंने कहा, मैं ऐसा कर सकता हूं। मैं ऐसा नहीं भी कर सकता। मेरा मतलब है, कोई नहीं जानता कि मैं क्या करने जा रहा हूं।

'सौदा न करने की गलती, अब पछतावा' : ट्रंप ने कहा, हमने 60 दिन तक इस मसले पर बात की, मगर आखिर में उन्होंने सौदा करने से इनकार कर दिया। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है।

बोले गृहमंत्री अमित शाह

देश में अंग्रेजी बोलने वालों को अपने ऊपर आएगी शर्म

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि भारतीय भाषाएं देश की आत्मा और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक हैं, और अब समय आ गया है कि हम अपनी भाषाई विरासत को दोबारा अपनाएं और दुनिया के सामने गवऱ् से आगे बढ़ें।

नई दिल्ली में पूर्व आईएएस अधिकारी आशुतोष अग्निहोत्री की पुस्तक 'मैं बूंद स्वयं, खुद सागर हूं' के विमोचन समारोह में बोलते हुए अमित शाह ने कहा, अब वह दिन दूर नहीं जब अंग्रेज़ी बोलने वालों को शर्म महसूस होगी, हमें ऐसा समाज बनाना है। बदलाव सिर्फ वे लोग ला सकते हैं जो ठान लेते हैं। मैं मानता हूं कि हमारे देश की भाषाएं हमारी संस्कृति के गहने हैं। अगर हमारी भाषाएं नहीं होंगी, तो हमारी भारतीय पहचान भी अधूरी रह जाएगी। शाह ने आगे कहा, अपने देश, संस्कृति, इतिहास और धर्म को समझने के लिए कोई विदेशी भाषा काफी नहीं है। मैं जानता हूं कि यह लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय समाज इसमें विजयी होगा।

ईरान के टॉप लीडर खामेनेई का यूपी से खास कनेक्शन

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। ईरान और इजरायल के बीच तेज होती जंग के बीच ईरान के शीर्ष नेता अयातुल्ला खामेनेई का भारत और उत्तर प्रदेश का कनेक्शन भी सामने आया है। ईरान के शीर्ष नेता अयातुल्ला खामेनेई के दादा सैयद अहमद मुसावी का जन्म 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में बाराबंकी के पास किंतूर गांव में हुआ था। अयातुल्ला खामेनेई के दादा सैय्यद अहमद मुसावी 1830 में किंतूर से ईरान गए थे। उनके पोते ने ईरान की तस्वीर बदल दी और अब उनके उत्तराधिकारी शासन कर रहे हैं।

ईरान के पहले सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई के पूर्वज बाराबंकी के गांव में रहते थे, खामेनेई के दादा सैयद अहमद मुसावी का जन्म 19वीं सदी की शुरुआत में बाराबंकी के पास किंतूर गांव में हुआ था। वह इस समय वहां के लोगों का शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने को काफी तत्पर थे और लोगों को काफी प्रोत्साहित भी किया। अभी भी उनके खानदान

के काफी लोग ईरान में हैं। बाराबंकी में खुमैनी के खानदान के डॉक्टर सैयद मोदम्मद रेहान काजमी ने बताया कि अभी भी हमारे काफी रिश्तेदार ईरान में हैं। हमारे चाचा नेहाल काजमी तो युद्ध से कुछ दिन पहले ही लौटे है। भाई आबिद अभी ईरान में ही हैं। ईरान में धर्मशास्त्र की शिक्षा ग्रहण कर रहे आबिद से डॉक्टर काजमी की बुधवार को ही बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी तो यहां थोड़ी शांति है, लेकिन अगर युद्ध भी होता है तो हम शहादत के लिए तैयार हैं। किंतूर गांव के प्रधान मोहम्मद अकरम ने बताया कि हमारी सोच अपने देश भारत के साथ है। वर्तमान में चल रहे युद्ध में हम लोग ईरान के साथ है। अमेरिका व इजरायल बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं। किंतूर गांव में रहने वाले आदिल खुमैनी के वंशज बताए जाते है।

करीब 230 वर्ष पहले 1790 में बाराबंकी के सिरौलीगौसपुर तहसील के किंतूर गांव के धार्मिक परिवार में सैय्यद अहमद मुसावी का जन्म हुआ था। 1830 में 40 वर्ष की उम्र में अहमद मुसावी अवध के नवाब के साथ धर्म यात्रा पर इराक गए थे। इराक से दोनों ईरान पहुंचे और अहमद मुसावी वहीं के एक गांव खुमैन में बस गए। अहमद मुसावी ने अपने नाम के आगे उपनाम हिंदी जोड़ा ताकि यह अहसास बना रहे कि वह हिंदुस्तान से हैं। इसके बाद लोग उन्हें सैय्यद अहमद मुसावी हिंदी के नाम से पहचानने लगे। अहमद मुसावी के परिवार में कई विद्वान हुए। उनके पोते रूहुल्लाह अयातुल्ला खामेनेई के नाम से मशहूर हुए। पिता की मौत के बाद मां और भाई ने मिलकर उन्हें पाला और पढ़ाया। रूहुल्लाह बहुत तेज थे। उन्होंने धर्म की पढ़ाई के साथ-साथ दुनिया के बड़े दार्शनिकों की किताबें भी पढ़ीं।

उस समय ईरान में पहलवी खानदान का राज था। राजा जनता पर जुल्म करता था। पश्चिमी देशों के इशारे पर चलता था। खामेनेई ने इसका खुलकर विरोध किया। इसके बाद राजा ने उन्हें देश से निकाल दिया। राजा ने सात जनवरी 1978 को ईरान के एक अखबार में खामेनेई को भारतीय एजेंट बता दिया। इसके बाद ईरान की सड़कों पर खामेनेई के पक्ष में आम लोग उतर आए। 16 जनवरी 1979 को राजा ईरान छोड़कर भाग गया। एक फरवरी 1979 को अयातुल्ला खामेनेई 14 वर्ष के बाद वापस ईरान आए। इसके बाद 11 फरवरी 1979 में ईरान में इस्लामी सरकार बनी। खामनेई ईरान के पहले सुप्रीम लीडर घोषित किए गए। अब मुसावी की चौथी पीढ़ी ईरान पर शासन कर रही है।

तबादले निरस्त

ट्रांसफर के लिए करोड़ों रुपये रिश्वत लेने का आरोप, होगी जांच

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। यूपी के स्टांप व रजिस्ट्रेशन विभाग में तबादलों के बदले रिश्वत लेने के मामले की जांच का आदेश दिया गया है और सभी ट्रांसफर निरस्त कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में स्टांप व रजिस्ट्रेशन विभाग में हुए 200 तबादलों को निरस्त करते हुए यह सत्र शून्य घोषित कर दिया गया है।

आरोप हैं कि तबादलों के लिए करोड़ों रुपये की रिश्वत ली गई है। मामले में स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने आईएएस समीर वर्मा के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। सभी 200 पदों पर ट्रांसफर और नियुक्तियों में करोड़ों रुपए लेने का आरोप लगा है। आदेश के बाद आईएएस के खिलाफ जांच शुरू होगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।